



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Me
26/3/99

सं० 17]
No. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 1999/चैत्र 2, 1921
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 1999/CHAITRA 2, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1999

सं. टी एम पी/1/97-के पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेश के अनुसार कांडला पत्तन न्यास के लिए भूमि की दरों को अंतिम रूप देने और निर्धारित करने के बारे में कांडला पत्तन न्यास के मामले को बन्द करता है।

मामला सं. टी एम पी/1/97-के पी टी

कांडला पत्तन न्यास (के पी टी)

...

प्राथी

आदेश

(22 फरवरी, 1999 को पारित)

कांडला पत्तन न्यास (के पी टी) ने कांडला में भूमि को पट्टे पर देने के लिए दरें नियत करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह बताया गया था कि सरकार द्वारा दरें पहले 1993-94 में अनुमोदित की गई थीं। दरों को संशोधित करने के प्रस्ताव पर पत्तन न्यास द्वारा गठित एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई थी।

2. प्रस्ताव की प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् के पी टी को कुछ अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जिनमें (क) विभिन्न श्रेणियों के लिए भूमि का वर्गीकरण (अर्थात् आवासीय, वाणिज्यिक, सेवा और औद्योगिक) और (ख) स्पष्ट संकल्पनाएं तैयार करने, उचित वर्गीकरण, तर्कसंगत परिभाषा आदि का कार्य शुरू करना शामिल था।

3. बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद के पी टी ने केवल यह विवरण दिया कि दर ढाँचा जलाग्र से स्थल की दूरी और गोदियों के आस-पास अधिक विकसित क्षेत्र से निकटता को ध्यान में रखते हुए किए गए वर्गीकरण पर आधारित है। उन्होंने भूमि का वर्गीकरण नहीं किया बल्कि यह कहा कि प्राधिकरण विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों से प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले उत्तरों के आधार पर कोई तर्क संगत निर्णय ले सकता है।

4. इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण की 22 फरवरी, 1999 को हुई बैठक में व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। यह नोट किया गया कि के पी टी को विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत भूमि के किसी युक्तिसंगत वर्गीकरण के आधार पर प्रस्ताव पुनः तैयार करने के लिए कहा गया था। के पी टी द्वारा यह कार्य

नहीं किया गया। यह समझा गया कि प्राधिकरण के लिए उचित वर्गीकरण, भूमि के प्रयोग की योजना आदि के बगैर दरें निर्धारित करना संभव अथवा उचित नहीं होगा। के पी टी प्राधिकरण से उस कार्य को करने की अपेक्षा नहीं कर सकता जो पट्टन न्यास द्वारा किया जाना है। प्राधिकरण के लिए अपने वर्तमान प्रारम्भिक स्तर पर किसी भी कीमत पर इन व्यौरों को तैयार करना संभव नहीं होगा। इस स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को पुनः तैयार करने के लिए वापस भेज देना ही अत्युत्तम कार्यवाही होगी। इस मामले को बन्द कर दिया जाना चाहिए और जब कभी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो तो एक नया मामला रजिस्टर किया जाए।

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/98]

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1999

No. TAMP/1/97-KPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case of the Kandla Port Trust about finalisation and fixation of rates of land for Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/1/97-KPT

The Kandla Port Trust (KPT)

...

Applicant

ORDER

(Passed on this 22nd day of February, 1999)

The Kandla Port Trust (KPT) submitted a proposal for fixation of rates for leasing of land at Kandla. It was stated that the rates were earlier approved by the Government in 1993-94. The proposal for revision of rates was mooted on the basis of the recommendations made by a Committee constituted by the Port Trust.

2. After a preliminary examination of the proposal, the KPT was requested to provide certain additional information/clarifications including (a) categorisation of land for various categories (viz., residential, commercial, service, and industrial) and (b) initiation of an exercise to prepare clear concepts, proper classification, logical definition, etc.

3. This requirement has not been fulfilled by the KPT in spite of repeated reminders. The KPT have merely come up with a statement that the rate structure is based on the classification done with respect to the distance of land from the waterfront and its proximity to the more developed area around the docks. They have not classified the land but have stated that the Authority can arrive at a logical conclusion based on the responses received by the Authority from various port users/representative bodies of port users.

4. The proposal was discussed in detail in the Authority's meeting held on 22 February 1999. It was noted that the KPT had been asked to re-formulate the proposal based upon some rational classification of the land under specific categories. This had not been done by the KPT. It was felt that it would not be possible or correct for the Authority to prescribe rates without proper classification, land use plan, etc. The KPT cannot expect the Authority to do what the Port Trust has to do. It will not be possible, at any rate at the present stage of its evolution, for the Authority itself to work out these details. In the event, it was decided that the best course of action would be to return the proposal for recasting. This case should be closed; a fresh case could be registered whenever the revised proposal was received.

[Advt./III/IV/Exty/143/98]

S. SATHYAM, Chairman